VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS 14 SEP 2018

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1153)

Name of Candidate	Ravi Kumar Sihag		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	168117
Center	MN	Date	14/09/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Highlighting the issues faced in BOT and EPC models of infrastructure investment, explain how HAM can address these. **(150 words) 10**

अवसंरचना निवेश के BOT एवं EPC मॉडल के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए व्याख्या कीजिए कि HAM इनका किस प्रकार समाधान कर सकता है।

अवसंरचना के विकास हेतु सरकारी क्षेत्रों की अपर्याप्तता के चलते निजी क्षेत्रों से सहयोग बढ़ाने (PPP) हेतु सरकार द्वारा विभिन्न मॉडल का प्रयोग किया गया है -

▷ BOT मॉडल :- बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर - इसमें निजी क्षेत्र सरकार की परियोजना का निर्माण, संचालन एवं कुछ समय तक वसूली कर सौंप देता है तथा सरकार निजी ऑपरेटरों को धन का भुगतान करती है

कमियाँ :- (i) मांग की कमी - परियोजना पर मिलने वाले लाभ का मुद्दा

(ii) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब

(iii) न्यायालयों में अटके मामले

(iv) बैंकों का भारी NPA एवं कंपनियों की द्वितुलनपत्र समस्या

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

EPC मॉडल :- इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन
इसमें सरकार भूमि अधिग्रहण व वित्त प्रबंधन करती है निजी क्षेत्र केवल प्रबंधन व निर्माण विशेषज्ञता तक सीमित होता है

कमियाँ (i) वित्त प्राप्त करने में कठिनाई।
(ii) हानि होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं
(iii) BOT संबंधी अन्य मुद्दे

HAM मॉडल :- हाइब्रिड एन्युटि मॉडल अर्थात सरकार प्रारंभिक वर्षों में योजना चालन का 40% भाग देगी व बाकी 60% भाग योजना के संचालन के दौरान होगा।

लाभ :- (i) निजी वित्त की कमी को सरकारी वित्त द्वारा दूर किया जायेगा।
(ii) लागत पूर्वानुमान संबंधी समस्याओं हेतु समाधान पक्ष
(iii) भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों का उलझाव नहीं होगा।

अतः उम्मीद है कि HAM मॉडल भारत के अवसंरचना विकास में नया आयाम पेश करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The investment rate in India has gradually declined after a historic high in the mid 2000s. Examine the reasons behind this trend. Discuss the steps required to revive investment for a sustained growth. **(150 words) 10**

भारत में निवेश दर, 21वीं सदी के प्रथम दशक के मध्य में एक ऐतिहासिक उछाल के उपरांत निरंतर घटती रही है। इस प्रवृत्ति के पीछे निहित कारणों का परीक्षण कीजिए। निरंतर वृद्धि हेतु निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिए।

निवेश दर के रुझानों पर बात करें तो यह 21वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में 38% तक बढ़कर 2016 में 32% के निम्न स्तर तक पहुंच गई है (आर्थिक समीक्षा 2017)।

कारण :- (i) उदारीकरण के फलस्वरूप 2011 में वृद्धि → निजी क्षेत्र में बूम

(ii) 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट के कारण बैंकों, कंपनियों पर दबाव

- वैश्विक मांग में कमी
- बैंक NPA में वृद्धि
- द्वितुलन पत्र की ~~समस्या~~ (TBS)

(iii) सरकारी व्यय में कमी का आना।

(iv) 2013 के समय 'मुद्रास्फीति' के कारण सोने, रियल एस्टेट में निवेश का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ना।
(V) बचत दर में कमी (बैंक ब्याजों की कम दरों के कारण)

आवश्यक कदम:-
(क) बैंको के बढ़ते NPA को हल करना
- दिवालियापन संहिता
- पुनर्पूंजीकरण पैकेज
(ख) - कॉर्पोरेट ऋण में वृद्धि करने के उपाय - कॉर्पोरेट बॉण्ड
- मसाला बॉण्ड
- बाह्य उधारी (ECB) के नये आयाम खोजना।
(ग) HAM, स्विस-चैलेंज मॉडल जैसे नये PPP मॉडल का विकास करना।
(घ) रिजर्व बैंक में सुधार कर सरकारी ऋण को मुद्रास्फीति मानकों से अलग करना।
(ङ) सोने, रियल एस्टेट निवेश में हतोत्साहन उपाय जैसे - सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना
इन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The measurement of the extent of formal sector and formal employment is yet an unsettled matter in our economy. Comment. Also, mention the steps which the government has taken to improve its extent. **(150 words) 10**

औपचारिक क्षेत्रक और औपचारिक रोजगार के विस्तार का मापन हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी एक अनसुलझा मामला है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इसके विस्तार में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन या अल्परोजगार के विवादों पर विचार करने से पहले रोजगार मापन को संबोधित करना जरूरी है-

संबंधित मुद्दे (क) भिन्न-भिन्न पद्धतियों से अलग-अलग परिणामों का आना जैसे- EPFO डाटा से रोजगार (औपचारिक क्षेत्र) -31% आता है तो जी.एस.टी. डाटा द्वारा 53%।

(ख) आँकड़ा संग्रहण पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव :- NSSO द्वारा छोटे स्तरों पर आँकड़ा लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक-रूप से अनुप्रयोग करने की प्रवृति

(ग) अनेक मंत्रालयों के अलग-अलग सर्वे में सहयोग का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुधार हेतु उठाये गये कदम :-

(क) नीति आयोग ने विभिन्न ऑकड़ा (स्त्रोत) प्रणालियों के अभिसरण व सहयोग की पद्धति को अपनाने पर बल दिया है।

(ख) विभिन्न तकनीकी पक्षों जैसे EPFO, जी. एस. टी. एन के डाटा का प्रयोग कर रोजगार निर्धारण का प्रयास करना।

(ग) 'रोजगार प्रोत्साहन योजना' के माध्यम से फर्मों को प्रोत्साहन देकर उनके डेटा के संग्रहण का प्रयास करना।

(घ) डाटा संग्रह को साप्ताहिक, मासिक वार्षिक तीन अवधियों में बाँटकर प्रयोग करना।

इसके अलावा नोबल पुरस्कार विजेता एंगस डिटन की ऑकड़ा संग्रहण विधि का प्रयोग करना भी उचित कदम होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Minimum Support Price (MSP) of crops is a short term solution for agricultural distress which creates long term problems. Examine. Suggest measures to overcome the the limitations of the MSP regime.**(150 words) 10**

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि संकट का एक अल्पकालिक समाधान है जो दीर्घकालीन समस्याएं पैदा करता है। परीक्षण कीजिए। MSP व्यवस्था की कमियों से निजात पाने हेतु उपाय सुझाइए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को संकट से बचाने का नीतिगत उपाय है जो विशेष परिस्थितियों में फसल मूल्यों के गिरने पर न्यूनतम मूल्य पर खरीद की गारंटी देता है -

अल्पकालिक समाधान के रूप में -

(क) किसानों को 'फसल मूल्य' की विसंगतियों से बचाता है।

(ख) विभिन्न फसलें उगाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

(ग) किसानों की फसलों की खरीद सुनिश्चित करता है

दीर्घकालीन समस्याएँ :- MSP की सामाजिक लागत - क्षेत्रीय असमानता

- विशेष फसलों जैसे चावल गेंहु कपास पर ही प्रभावी जिस कारण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

फसल विविधीकरण को हतोत्साहन।
- एकफसली प्रारूपण के कारण मृदा ह्रास, प्रदूषण, कीटनाशकों व उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग। पंजाब में बिजली पानी का भारी अपव्यय (गेहूं पर MSP के कारण)।

उठाये गये कदम :- (i) हालिया गेहूं चावलों के अलावा अन्य फसलों पर तय किया गया मूल्य।
(ii) सरकार द्वारा जलवायु स्मार्ट कृषि, फसल विविधीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन।
(iii) सब्सिडी के बजाय निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना।
(iv) अन्य मॉडलों (प्रापण के) जैसे मूल्य डेफिसिएन्सी मॉडल, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन उदा० मध्यप्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना।
(v) फूलों, सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन इंडिया फंड, FDI उद्योगों को बढ़ाना आदि)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Enumerating the factors that determine a nation's energy-mix, comment on the need for having a diversified fuel basket for meeting India's future energy demands. **(150 words) 10**

किसी राष्ट्र के ऊर्जा-समिश्र (एनर्जी-मिक्स) को निर्धारित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करते हुए, भारत की भावी ऊर्जा मांगों को पूरा करने हेतु एक विविधिकृत फ्यूल बास्केट के होने की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।

किसी भी राष्ट्र के ऊर्जा-समिश्र से तात्पर्य ऊर्जा के उन विभिन्न स्रोतों के विकास, स्थापना व प्रयोग से है जिन्हें वह राष्ट्र जनता की ऊर्जा सुरक्षा हेतु प्रयोग में लाता है उदा० भारत का ऊर्जा समिश्र अधिक जीवाश्म ईंधन उन्मुख है।

निर्धारित करने वाले कारक:-

(क) प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता
उदा० खाड़ी देशों में तेल।

(ख) जनसंख्या का आकार

(ग) अर्थव्यवस्था का प्रकार - प्राथमिक गतिविधि केन्द्रित या उद्योग आधारित

(घ) तकनीक की उपलब्धता (वैकल्पिक स्रोतों के विकासार्थ

(ङ) बाहरी कारण जैसे विश्व की भू-

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनैतिक परिस्थितियाँ

(ह) स्थलाकृति - जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के विकास हेतु।

विविधीकृत फ्यूल बास्केट की आवश्यकता

(क) अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ उद्योग, घरेलू एवं यातायात मांग बढ़ रही है।

(ख) विभिन्न योजनाओं जैसे उजाला, उज्ज्वला के क्रियान्वयन हेतु।

(ग) अस्थिर मध्य-पूर्व के कारण भारत को अन्य स्रोतों पर विचार करना चाहिये।

(घ) पेरिस जलवायु समझौते के INDC को पूरा करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना होगा।

(ङ) आयात बिल को नियंत्रित करने हेतु जीवाश्म ईंधन आधारित बास्केट को नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बास्केट में परिवर्तित करना।

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से बास्केट में विविधीकरण आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Air quality in Indian households, especially in rural areas, is lethal due to a number of factors. In this context, highlighting the challenges faced in improving indoor air quality, enumerate the measures that can be taken to address them. **(150 words) 10**

भारतीय घरों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वायु की गुणवत्ता कई कारकों से प्राणघातक है। इस संदर्भ में, घरों के भीतर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने में सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उनसे निपटने हेतु अपनाये जा सकने वाले उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

आंतरिक वायु प्रदूषण से तात्पर्य है घरों के भीतर विभिन्न गैसों, प्रदूषकों से वायु की गुणवत्ता में होने वाला अवांछित परिवर्तन।

कारण :-

(क) पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता → अधिक धुँआ।

(ख) वातन की कमी।

(ग) रेडॉन आदि गैसों का निकलना।

(घ) तंबाकु प्रयोग से पैसिव स्मोकिंग के कारण स्वास्थ्य प्रभाव।

(ङ) अदक्ष विद्युत उपकरणों, वायरों से निकलने वाली जहरीली गैसें।

सुधार के समक्ष चुनौतियाँ :-

(i) ग्रामीण भारत में अभी भी बड़ी जनसंख्या पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्भर।

(ख) अनियंत्रित शहरीकरण ने गैर-योजना कृत मकानों का निर्माण किया है।

(ग) स्वच्छता मानकों एवं जनता में जागरूकता का अभाव है।

(घ) शहरों में ~~[illegible]~~ वातायन की समस्या।

उपाय :-

(i) हरित बिल्डिंग कोड का क्रियान्वयन करना।

(ii) घरों में खिड़कियों, रोशनदानों की संख्या बढ़ाना।

(iii) ग्रामीण ईंधन सुधार हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।

(iv) घरों में तम्बाकू, सिगरेट का प्रयोग कम करना।

(v) भवन निर्माण सामग्रियों की स्वच्छता एवं मानकीकरण पर बल देना ताकि उनमें रेडियो-एक्टिव पदार्थ न हो।

इन उपायों एवं जन-जागरूकता द्वारा हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

7. Highlight the characteristics and applications of Cyber Physical systems. Also, enumerate the various objectives of the Cyber Physical Systems programme recently launched by the government. **(150 words) 10**

साइबर भौतिक प्रणालियों (साइबर फिजिकल सिस्टम) की विशेषताओं और अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, हाल ही में सरकार द्वारा आरंभ किए गए साइबर भौतिक प्रणाली कार्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए।

साइबर फिजिकल सिस्टम से तात्पर्य ऐसे तंत्र से है जो कम्प्यूटर एवं भौतिक तंत्रों के मेल-जोल द्वारा विभिन्न कार्यों का निष्पादन करते हैं जैसे - रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक चालक रहित कारें, मेट्रो सिस्टम आदि।

अनुप्रयोग

(क) उद्योग में - औद्योगिक क्रान्ति 4.0 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ इन सिस्टम्स का प्रयोग होगा।

(ख) कृषि में :- पूर्वानुमान कृषि, डाटा संग्रहण कीटनाशक, उर्वरकों के प्रयोग में विभिन्न यंत्रों द्वारा

(ग) यातायात - ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रबंधन, चालक-रहित कारें, मेट्रो, स्मार्ट रेलवे में।

(घ) स्वास्थ्य :- मरीजजाँच प्रणाली, डाटा प्रबंधन, रेफरल प्रणाली में प्रयोग।

सरकारी प्रयास :- सरकार ने हाल में देश में विभिन्न क्षेत्रों में 25 सा०कि०सि० स्थापित करने का निर्णय लिया है
- बजट 2018 में भी प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य :- देश में डिजीटल इंडिया, मेक इन इंडिया एवं अन्य कार्यक्रमों को त्वरित करने के साथ-साथ तकनीक के स्मार्ट प्रयोग द्वारा गुणवत्ता सुधार।
- देश में अनुसंधान कार्यों में वृद्धि
- उद्योग-अकादमिक सहयोग बढ़ाना,
- डेटा संग्रहण करने हेतु।

इन प्रयासों से निश्चित रूप से देश में तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. India needs to collaborate and participate in international scientific projects in order to place itself as a major player in cutting edge research. Discuss in the light of ongoing global mega science projects. **(150 words) 10**

कटिंग एज रिसर्च में स्वयं को एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में स्थापित करने हेतु भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं (इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स) में सहयोग करने और भाग लेने की आवश्यकता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जारी मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स के आलोक में चर्चा कीजिए।

कोई भी वैज्ञानिक परियोजना के एक देश के हाथों सफल होने के कम आसार होते हैं। इसलिए विभिन्न देशों का सहयोग व भागीदारी आवश्यक हो जाते हैं। इसके निम्न लाभ होते हैं -

(i) विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं की पूलिंग से विशेषज्ञता का लाभ।

(ii) दोनों देशों के ज्ञान का आदान-प्रदान।

(iii) प्रोजेक्ट में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण में लाभ।

(iv) वित्तीय आवंटन में भागीदारी से वित्तीय भार में कमी आती है।

विश्व के प्रमुख मेगा साइंस प्रोजेक्ट जैसे -

- CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- 30 मीटर दूरबीन प्रोजेक्ट (हवाई द्वीप पर)
भारत, चीन, जापान अमेरीका

- ITER प्रोजेक्ट जो कि नाभिकीय संलयन से विद्युत उत्पन्न हेतु।

→ लीगो प्रोजेक्ट (अमेरीका)

-

इन प्रोजेक्ट में कुछ में तो भारत भागीदारी कर रहा है किन्तु कुछ परियोजनाओं में भारत की भागीदारी कम है क्योंकि -

- भारत में विशेषज्ञता के साथ प्रोत्साहन का अभाव है।
- भारत का अनुसंधान - विकास व्यय GDP का केवल 0.7 % है (इजराइल का 4.3 %)
- जनता में वैज्ञानिक रुझानों की कमी

अत: इन सभी समस्याओं का समाधान कर सहयोग के लाभों के अर्जन हेतु वैश्विक सहयोग व भागीदारी जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Deployment of central armed forces in states has been a contentious issue. Mention the issues involved and suggest some remedial measures.

(150 words) 10

राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसमें सम्मिलित मुद्दों का उल्लेख कीजिए और कुछ सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 355 के तहत केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्यों के सुरक्षा करे।

इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत कई बार ज़रूरी कारकों से तो कई बार गैर-आवश्यक कारकों से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स आदि की तैनाती राज्यों में कर दी जाती है।

संबंधित मुद्दे

(क) संघात्मकता की भावना के विरुद्ध।

(ख) कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है।

(ग) बलों की तैनाती आजकल राजनीति प्रेरित अधिक होती है, सुरक्षा प्रेरित कम।

(घ) राज्य की पुलिस बलों पर केन्द्रीय

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बलों के अधिकारियों द्वारा दबाव।
- सहायिकी के सिद्धान्त (principle of Subsidiarity) के खिलाफ क्योंकि राज्य की समस्याएँ राज्य बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं।
- विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध।

उपाय :- पुंछी आयोग (2007) की सिफारिशों को लागू किया जाये
- गैर ज़रूरी तैनाती न हो।
- राज्य की मंजूरी के बिना तैनाती न हो।

(ii) विशिष्ट कारणों जो तैनाती हेतु आवश्यक हों, उनका उल्लेख किया जाये।

(iii) राज्यपुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाये न कि केन्द्रीय हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाये।

(iv) अनु० 355 में संशोधन हेतु चर्चा की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त उपाय केन्द्र-राज्य तनाव को कम किया जा सकता है।

10. In what ways does the physiography of India pose a challenge to its counter-terrorism efforts? What can be done to deal with these challenges? **(150 words) 10**

भारत की भूआकृति किस प्रकार इसके आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करती है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

भारत की भौगोलिक सीमा अत्यन्त लंबी है (15000 किमी लगभग) । इतनी लंबी सीमा - शत्रु पड़ोसी देशों की उपस्थिति एवं सीमा विवाद तथा देश के मध्य विद्यमान विविधता के फलस्वरूप उत्पन्न आतंकवाद के सम्मुख चुनौती उत्पन्न करती है

(क) दुर्गम भू-आकृति होने के कारण कश्मीर उत्तर-पूर्व में राज्य प्रेरित आतंकवाद (पाकिस्तान, चीन) से है।

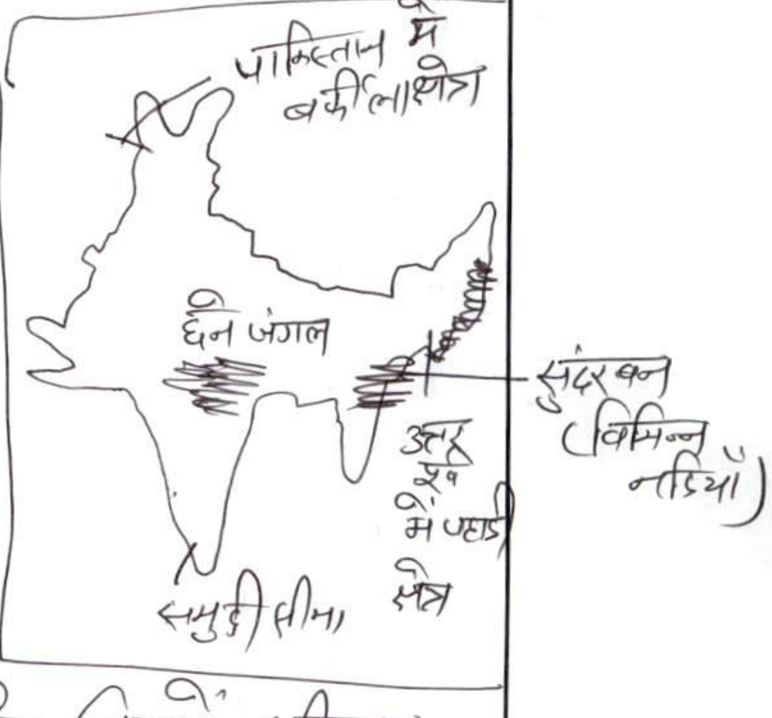

(ख) दुर्गम भू-आकृति सीमा रेखा की अस्पष्टता बढ़ाती है जिसमें सीमा विवाद नहीं सुलझ पाते - उदा० के लिए

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत - पाक, भारत - चीन विवाद।

(ग) उत्तर-पूर्व के घने जंगल आतंकियों के छिपने का उचित आश्रय उपलब्ध कराते हैं।

(घ) छिद्रित सीमाओं के कारण आतंकवादियों का परदेश गमन हो जाता है।

(ङ) लंबी तटीय रेखा - समुद्री आतंकवाद उदा० के लिए 2008 के मुंबई ब्लास्ट।

उपाय :-

(क) विभिन्न सीमा विवादों को सुलझाना उदा० 2015 में बांग्लादेश के साथ सुलझाया।

(ख) तकनीक का प्रयोग :- पाकिस्तान के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) एकीकृत चेक पोस्ट, ड्रोन का प्रयोग, लेजर अवरोधक को सुदृढ़ बनाना

(ग) स्थानीय लोगों व आसूचना को प्रभावी बनाना जैसे विलेज वॉलंटियर फोर्स ताकि भू-आकृति की जानकारी मिले।

(घ) बॉर्डर के पास अवसंरचना विकास सड़क, मोबाइल टावर आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Enhancing private infrastructure spending and revival of stalled projects is critical to the success of Bharatmala Pariyojana. Discuss. Also enumerate measures taken by the government to revive stalled projects on National Highways. **(250 words) 15**

निजी अवसंरचना व्यय में वृद्धि एवं अवरुद्ध परियोजनाओं का पुनरुद्धार भारतमाला परियोजना की सफलता हेतु महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबद्ध अवरुद्ध परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए।

हाल ही में भारत सरकार ने सड़कों की परियोजनाओं को त्वरित करने के लिये भारतमाला नामक अम्ब्रेला योजना का निर्माण किया है। इस योजना के तहत आगामी वर्षों में 5.35 लाख करोड़ के बजट के साथ 35 000 किमी सड़क निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित है। परियोजना की सफलता हेतु दो मुद्दे निम्न है-

निजी अवसंरचना व्यय में वृद्धि : परियोजना में सड़क निर्माण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नीलामी के तहत निजी ठेकेदारों को प्रदान किया जायेगा, इसके निम्न लाभ होंगे।

- निजी विशेषज्ञता का लाभ।

- वित्त की पूलिंग हो जायेगी।
- सरकारी राजकोषीय खाते पर कम प्रभाव पड़ेगा।
- कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा विभिन्न कारकों जैसे -
- पर्यावरणीय मंजूरी
- न्यायालयों की दखलंदाजी
- स्थानीय विरोध
- भूमि अधिग्रहण
- एन.पी.ए की समस्या के कारण अनेक परियोजनाएँ अवरुद्ध पड़ी हैं।

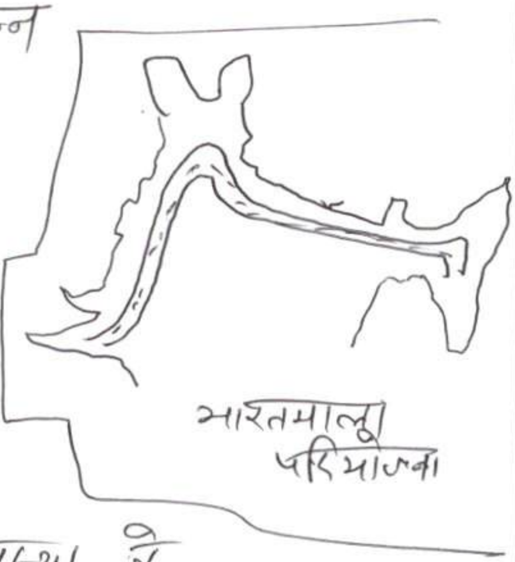

इनके पुनः संचालन से एक ओर तो कंपनियों का वित्त प्रवाह बढ़ेगा दूसरा पहले से योजना बनाई गई परियोजनाएँ भी चल पायेंगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकारी कदम :-

(क) 'राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश प्रकोष्ठ' की स्थापना।

(ख) हाइब्रिड-एन्युटी मॉडल जैसे निवेश प्रक्रियाओं का विकास।

(ग) I-NAM Pro. जैसे तकनीकी नवाचार।

(घ) सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्युटस की स्थापना।

(ङ) अवरुद्ध परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बैंकों की क्षमता सुधार हेतु पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम, बैंकों का विलयन इत्यादि

(च) लॉजिस्टिक को अवसंरचना का दर्जा देना।

इस प्रकार उपर्युक्त उपायों के साथ न्यायालयों में लंबित वादों हेतु स्पेशल कोर्ट का निर्माण व पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया का सरलीकरण भी आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. In the light of increasing NPAs and frauds, the twin balance sheet problem has grown immensely. Comment on the issue and analyse the potential of the Insolvency and Bankruptcy Code to be a game changer for Indian economy's health and long-term growth. **(250 words) 15**

NPAs एवं धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के चलते, दोहरे तुलन पत्र (ट्विन बैलेंस शीट) की समस्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस मुद्दे पर टिप्पणी कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दीर्घकालिक संवृद्धि के लिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता में एक गेम चेंजर होने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

दोहरे तुलन पत्र की समस्या से अभिप्राय है कि एक ओर तो बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के वापिस न आने से उनकी बैलेंस शीट पर दबाव तो दूसरी ओर कॉर्पोरेट क्षेत्रों में मंदी के कारण उनकी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर दबाव का बढ़ना।

21वीं सदी के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था की उच्च संवृद्धि दर के कारण ऋणों की मात्रा में वृद्धि हुई। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट ने वैश्विक मांग में अचानक कमी ला दी। इस परिस्थिति में कंपनियों की परिसंपत्तियाँ दबाव में आ गई एवं बैंकों के दिये ऋण भी वापिस नहीं आ पाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके अलावा विभिन्न धोखाधड़ी जैसे किंगफिशर मामला एवं हालिया नीरव मोदी मामले ने बैंकों की कमर तोड़ दी।

ऋण उगाही की जटिल प्रक्रिया के कारण बैंकों पर दबाव भी बढ़ा है।

इसी सन्दर्भ में दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जैसे-

(क) इसमें लेनदारों जैसे बैंक, वित्तीय कंपनियाँ, अन्य आपूर्तिकर्ता को प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया गया है

(ख) निश्चित समय सीमा (180 दिन अधिकतम 270 दिन)

(ग) दिवालियापन एवं लिक्विडेशन से पहले संवाद हेतु दिवालिया पेशवर की नियुक्ति का प्रावधान। यह पेशवर दोनों पक्षों में बात कर वैकल्पिक उपाय जैसे 5/25

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

योजना आदि सुझा सकता है।
(घ) सभी लेनदारों को एक मंच पर लाकर समिति बनाने का प्रावधान इसके निश्चित मतों से प्रक्रिया का प्रारम्भ होना।)

चुनौतियाँ:- (i) दबावग्रस्त कंपनी को अपना पक्ष रखने का समय कम (प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का अतिक्रमण)
(ii) कंपनी के दबावग्रस्त होने के बाह्य कारण भी हो सकते हैं।
(iii) भारत में कुशल दिवालिया पेशेवरों का अभाव है।
(iv) NCLT व ~~DE~~ DRT में कर्मचारी व कार्यबलों का अभाव।
(v) छोटे लेनदारों (1 लाख ₹ से अधिक) भी प्रक्रिया की शुरुआत कर कंपनी पर दबाव बना सकते हैं।

- अतः 13.6% NPA वाले सार्वजनिक बैंकों पर दबाव कम करने हेतु यह निश्चित ही प्रभावी है, साथ ही मध्यम मार्गों हेतु 'प्रोजेक्ट सशक्त' जैसे उपाय भी स्वागत योग्य हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Highlight the importance of MSME sector in India's economy. Also, identifying the challenges, suggest some policy recommendations to ensure their sustenance and competitive growth. **(250 words) 15**

भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्रक के महत्व पर प्रकाश डालिए। साथ ही, चुनौतियों की पहचान करते हुए उन्हें संपोषित करने और उनके प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतिगत अनुशंसाओं का सुझाव दीजिए।

भारत में लगभग 5.11 करोड़ एम. एस. एम ई. कार्यरत हैं। इन क्षेत्रकों का अर्थ है एक निश्चित निवेश के आधार पर उद्योगों का विभाजन करना।

अर्थव्यवस्था में महत्व

(i) भारत के 70% से अधिक रोजगार 20 से कम संख्या वाली फर्मों में।

(ii) उपर्युक्त 5.11 करोड़ उद्योगों ने लगभग 12 करोड़ रोजगार दिए हैं।

(iii) भारतीय जी.डी.पी. में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान।

(iv) भारतीय कुल निर्यात में 45% का योगदान देना।

(v) पारंपरिक ज्ञान व स्थानिक विशेषज्ञताओं के पोषक।

चुनौतियाँ :-
(क) बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा
(ख) ऋण मिलने की समस्या
(ग) तकनीकों का अभाव
(घ) बड़ी कंपनियों के समान इनके पास उपभोक्ता व्यवहार को जानने; निवेश के भावी प्रभावों का विश्लेषण करने एवं बाजार के अनुसार उत्पादों में परिवर्तन व ब्रांडिंग के लिये विशेषज्ञ कार्यबल एवं प्रबंधक नही होते हैं।
(ङ) फॉरवार्ड व बैकवार्ड लिंकेज का अभाव
(च) जी.एस.टी. व्यवस्था में भी छूट की सीमा को कम कर 20 लाख करना (पहले 1.5 करोड़)
(छ) बड़ी कंपनियों को आपूर्ति हेतु संपर्कों का अभाव

अनुशंसाएँ (क) हालिया सूक्ष्म लघु एवं

मध्यम उद्योग बिल' को पारित करना जिससे इन वर्गीकरण आधुनिक मानकों के अनुरूप हो सके। (जी. एस. टी)

2) बड़ी कंपनियों से संपर्क सुधारार्थ लिंकेज हेतु MSME संबंध, MSME समाधान (विवाद समाधान) जैसे नवाचारों को प्रोत्साहन देना।

3) निर्यात नीति में उचित सुधार कर टैरिफ दरों को युक्ति संगत बनाना।

4) ऋण व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मुद्रा बैंक, स्टैंड-अप इंडिया जैसे प्रोत्साहनों का प्रभावी क्रियान्वयन

5) ग्रामीण अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स में निवेश को बढ़ाकर इनकी लिंकेज में सुधार करना।

6) ZED योजना (जीरो डिफेक्ट) को प्रोत्साहन

इस प्रकार इन उपायों की मदद से इन उद्योगों की क्षमता व वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Going forward, the allied sectors will play a critical role in increasing the resilience and improving economic returns in agriculture. Discuss.

(250 words) 15

आगामी समय में, संबद्ध क्षेत्रक कृषि में लचीलापन बढ़ाने एवं आर्थिक प्रतिफल में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चर्चा कीजिए।

कृषि के संबद्ध क्षेत्रकों से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रकों से है जो प्रत्यक्षतः कृषि या प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं जैसे- दुग्ध उत्पादन, पशुधन पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन।

संबद्ध क्षेत्र: लचीलापन बढ़ाने में उपयोगी

1) कृषि में फसल प्रणाली में निहित अनिश्चितता के खतरों पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण जैसे- सूखा पड़ने पर फसल नष्ट होने पर भी सूखी चारे की मात्रा द्वारा पशुपालन किया जा सकता है।

2) बाजार व्यवस्था के खतरों फसलों के दामों में अचानक आयी कमी की पूर्ति इन उत्पादों - दुग्ध, अंडों की

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बिक्री द्वारा रोकी जा सकती है
3) फसलों में विविधीकरण बढ़ाने में ~~आत्म~~ मददगार। उदा० पशुधन का चारे की थोड़ी फसल बोकर अन्य फसलों के साथ किया जा सकता है।
4) हालिया सरकारी प्रोत्साहनों में वृद्धि।
5) इन क्षेत्रकों में सहकारिता का लाभ भी उठाया जा सकता है।

आर्थिक प्रतिफल में सुधार

(क) जहाँ फसलों में उपभोक्ता कीमत का 25% ही किसान को मिलता है वहीं दूध में लगभग 75% कीमत की प्राप्ति होती है।
(ख) फलों, सब्जियों का उत्पादन लगातार 5 वर्षों से फसलों से अधिक है। फलों का मूल्य भी अधिक होता है। हालिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहनों (PM किसान संपदा योजना) के कारण

किसानों की लाभप्रदता के अवसर बढ़ जाते हैं।

3) अतिरिक्त सहायकों या विशेषज्ञों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उदा० मुर्गीपालन

4) निर्यात के अवसरों का अधिक होना।

इन सबके अतिरिक्त यदि घरेलू स्तर पर न कर सहकारी या लघु उद्योगों के स्तर पर भी इस प्रकार के उद्योग लाभकारी है - उदा० के लिये गुजरात का अमूल मॉडल।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. What do you understand by Seed Replacement Rate? Explaining the concept of breeder, foundation and certified seeds, highlight the major policy initiatives taken in order to address the challenge of quality seed availability to farmers. **(250 words) 15**

बीज प्रतिस्थापन दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) से आप क्या समझते हैं? ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, किसानों के लिए गुणवत्तापरक बीजों की उपलब्धता की चुनौती का समाधान करने हेतु की गई प्रमुख नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालिए।

बीज प्रतिस्थापन दर से अभिप्राय है प्रमाणित बीजों एवं फॉर्म सेवड. बीजों का अनुपात अर्थात् किसान ने कितनी मात्रा में प्रमाणित बीजों का प्रयोग, खेत पर बचाये हुए बीजों के सापेक्ष किया है।

बीज प्रतिस्थापन दर = प्रमाणित बीज / फॉर्म सेवड. सीड्स

ब्रीडर	फाउंडेशन	प्रमाणित बीज
- प्रयोगशाला में निर्माण उदा० ICAR के द्वारा	- उद्योग व कंपनियों द्वारा ब्रीडर बीजों से निर्माण	- कंपनियों द्वारा किसान उत्पादक संगठनों एवं अन्य किसानों को प्रोत्साहन
- शुद्धता लगभग शत प्रतिशत।	- शुद्धता प्रतिशत तुलनात्मक कम	

देकर खेतों में विशिष्ट परिस्थितियों में फाउंडेशन बीजों से प्रामाणिक बीजों का निर्माण किया जाता है। इनकी शुद्धता बाकी दोनों से कम होती है

चरण

ब्रीडर बीज → फाउंडेशन बीज → प्रामाणिक बीज

किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करने की चुनौतियाँ

(क) जागरूकता का अभाव।
(ख) बीजों का मंहगा होना।
(ग) नकली बीजों की समस्या।
(घ) आपूर्ति पक्ष से संबंधित चुनौतियाँ जैसे बीजों की कम मात्रा, अनुसंधानों का अभाव आदि।

प्रमुख नीतिगत पहलें:
(क) किसानों की जागरूकता वृद्धि हेतु संचार

का प्रयोग - टोल फ्री नम्बर 1551 तथा बायोटेक किसान प्लेटफॉर्म आदि नवाचार।

(ख) किसानों हेतु प्रजनक के बौद्धिक संपदा अधिकार ~~बिल~~ अधिनियम को पारित करना।

(ग) बीजों को सस्ते में प्रदान करने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना। |

(घ) आपूर्ति पक्ष पर नकली बीजों पर लगाम लगाना। बीजों की उपलब्धता बढ़ाना

(ङ) नई बीज प्रजातियों जैसे सांभा मंसूरी (चावल), विवेक-9 (मक्का) का विकास।

अन्यउपाय :- बीज अधिनियम 2004 को पारित करना चाहिये।

राष्ट्रीय बीज नीति 2009 का अक्षरशः क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. While overcrowding in public places cannot be wished away in India, what we need are better infrastructure and more effective crowd-control measures. Comment. Also, briefly enumerate NDMA guidelines for crowd management. **(250 words) 15**

यद्यपि भारत में सार्वजनिक स्थलों पर अत्यधिक भीड़भाड़ को कम नहीं किया जा सकता है, तथापि हमें बेहतर अवसंरचना और अधिक प्रभावी भीड़-नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, भीड़ प्रबंधन के लिए NDMA के दिशानिर्देशों को संक्षेप में सूचीबद्ध कीजिए।

कुछ समय पहले बिहार की भगदड़ हो या कुछ वर्ष पहले राजस्थान में माता के मंदिर में अनेक लोगों की मौत – भारत में भगदड़ व भीड़ प्रबंधन की चुनौतियाँ पेश करते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिये निम्न उपायों का प्रयोग किया जा सकता है।

अवसंरचनात्मक पक्ष

(क) लोगों के गुजरने के रास्तों को विस्तृत करना।

(ख) यातायात पर नियंत्रण बनाये रखना।

(ग) विभिन्न पुलों आदि पर संख्या से अधिक भीड़ की अनुमति न देना साथ ही इनकी मजबूती का उचित ढंग से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सत्यापन कर लेना।

नियंत्रण पक्ष :- भीड़ स्थलों पर तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है जैसे -
- आने वाले यात्रियों की संख्या को रेलवे आदि के आँकड़ों से मिलाकर बिग डेटा एनालिसिस करना।
- स्थलों पर ड्रोन का प्रयोग, लाउडस्पीकरों के प्रयोग द्वारा निगरानी।
- विभिन्न स्थलों पर सी.सी.टी.वी. का प्रयोग

② उचित कार्यबल की तैनाती करना
③ बड़े वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित कर केवल पैदल यात्रियों को मंजूरी प्रदान करना।
④ यात्रियों व नियंत्रक अधिकारियों हेतु उचित दिशा-निर्देशों की सूची तैयार करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

NDMA के दिशा निर्देश :-

(क) किसी भी पर्व, त्यौहार से पूर्व भीड़ स्थल का उचित जायजा लेना।

(ख) संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व ट्रैफिक प्रबंधन।

(ग) विभिन्न हितधारकों के साथ लेकर यात्री क्षमता आकलन।

(घ) विभिन्न अवसंरचनात्मक संरचनाओं की मजबूती का जायजा लेना।

(ङ) अफवाहों के निराकरण हेतु तंत्र का निर्माण करना।

(च) भगदड़ की स्थिति में मीडिया की भूमिका व विनियमन।

(छ) भीड़ के आपातकालीन स्थिति में हिटाना व बचाव उपाय।

इन सभी निर्देशों द्वारा भीड़ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर जन-धन हानि को रोका जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Processing and safe disposal of garbage must replace the current model of landfills in order to transform our cities to being 'smart'. Elucidate. In this context, analyse the reasons for failure of waste management policies in India. **(250 words) 15**

हमारे शहरों को 'स्मार्ट' बनाने के लिए भूमिभराव (लैंडफिल) के वर्तमान मॉडल को अपशिष्ट के प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों की विफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

भूमिभराव से तात्पर्य है कचरे को एक निश्चित स्थान पर भूमि में गड्ढा बनाकर डंप करना एवं वहीं पर सड़ने गलने के लिये छोड़ देना। इस विधि की निम्न हानियाँ है-

(क) कचरे में निहित हानिकारक पदार्थों की लीचिंग से जल व मृदा प्रदूषण।

(ख) कचरे का रीयूज, रिसाइकिल नहीं हो पाता।

(ग) कचरे के सड़ने गलने से भारी मात्रा में गैस व दुर्गंध निकलती है, जो वातावरण दूषित करती है।

(घ) शहरी सौन्दर्य में कमी।

(ङ) कचरा बीनने वालों के स्वास्थ्य

पर दुष्प्रभाव।

इस विधि के बजाय यदि कचरे को प्रसंस्कृत किया जाये एवं सुरक्षितनिपटान किया जाये तो निम्न लाभ होंगे।

- भारतीय शहर प्रतिवर्ष 1,50,000 टन कचरे का उत्पादन करते हैं। प्रसंस्करण से कचरे की मात्रा में कमी आयेगी।
- कुछ लाभकारी पदार्थों का पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा।
- रीड्यूस, रीयूज, रीसाइकल चक्र का प्रयोग होगा (3R)
- निपटान :- कचरे से ऊर्जा (नीति आयोग की योजना)
- बायो गैस निर्माण
- कचरा निस्तारण की विकेन्द्रित व्यवस्था को प्रोत्साहन देना।
- कचरे को संसाधन मानना

इन सभी उपायों से एवं केरल के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अल्लापुझा शहर, पुणे के पिंपरीवाड़ क्षेत्र व गुजरात के राजकोट मॉडल का प्रयोग भी किया जा सकता है।

अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों की विफलता के कारण

(क) स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव।

(ख) जागरूकता की कमी।

(ग) केन्द्रीकृत एप्रोच का रखा जाना, सामुदायिक भागीदारी पर बल न देना।

(घ) कचरा प्रबंधन में तकनीक व नवाचार पर बल न देना।

(ङ) वेस्ट टू एनर्जी के प्रति स्थानीय समुदायों की शिथिल प्रतिक्रिया।

(च) कचरा बीनने वालों का रोजगार पक्ष।

(छ) कठोर दंडात्मक प्रावधानों को लागू न किया जाना।

(ज) अभिवृत्ति संबंधी कारक (Attitude)

इन सभी कारकों से शहरों में कचरा प्रबंधन अभी भी बड़ी समस्या है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What do you understand by TRIPS plus provisions being advocated by developed countries outside the WTO based TRIPS agreement? Do you think India should show some flexibility and incorporate certain TRIPS plus provisions in its IPR regime? **(250 words) 15**

विकसित देशों द्वारा WTO आधारित ट्रिप्स (TRIPS) समझौते से बाहर अनुशंसित किए जा रहे ट्रिप्स-प्लस प्रावधानों से आप क्या समझते हैं? क्या आपके विचार से भारत को कुछ लचीलापन दिखाना चाहिए एवं अपनी IPR व्यवस्था में कुछ ट्रिप्स-प्लस प्रावधानों का समावेश करना चाहिए?

ट्रिप्स-प्लस प्रावधान 'व्यापार आधारित बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS)' का अगला चरण है जो कि बौद्धिक संपदा के सृजकों के अधिकारों में वृद्धि कर इससे संबंधित कानूनों में कठोरता लाने का एक विचार है। मुख्यतः विकसित देश इस संबंध में मांग कर रहे हैं।

इसमें आने वाली मुख्य तीन बातें निम्न हैं-

(क) ब्रॉडकास्टर / ~~वेब~~ वेबकास्टर के अधिकारों में वृद्धि करना।

(ख) पुराने बौद्धिक संपदा अधिकारों में वृद्धि कर इन्हें और अधिक कठोरता

से लागू करना।

(ग) अधिकारों की रक्षा हेतु 'धोखाधड़ी विरोधी कानून' (Anti - circumvence Law) को पारित करना।

भारतीय पक्ष :- विकसित देशों के अनुसार इनसे विकासशील देशों को ही फायदा होगा क्यों कि -

- इनसे विकासशील देशों में FDI में वृद्धि होगी।
- अधिक कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार अधिक अनुसंधान नवाचारों को प्रेरित करेंगे।
- विकासशील देशों के व्यापर निवेश में वृद्धि के साथ तकनीकी स्थानान्तरण तंत्रों का विकास हो पायेगा।

इन सभी लाभों के साथ-साथ भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ भी है जैसे

(क) अधिक कठोर अधिकारों का सीधा संबंध अधिक नवाचार से हो यह आवश्यक नहीं है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसे अधिकार एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है।

(ग) डाटा अनन्यता (Data exclusivity) की नीतियाँ उत्पादकों के उत्पादों की गुणवत्ता को कम कर सकती है।

(घ) विकसित देशों द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों के जरिये भारतीय निर्यात को प्रतिबंधित। प्रभावित किया जा सकता है।

(ङ) मंहगी तकनीक स्थानान्तरण प्रक्रिया।

चूंकि भारत ने अपनी IPR नीति व कानूनों द्वारा पुराने ट्रिप्स समझौतों का पालन किया है, इसके साथ-साथ भारत एक विकासशील देश भी है, अतः भारत को चाहिये कि इन सुधारों को त्वरित न अपनाकर धीरे-धीरे अपनाये ताकि बौद्धिक अधिकार संरक्षण के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) has pitched for the need of an integrated approach in order to address the difficulties in preventing, detecting, investigating and prosecuting Transnational Organised Crimes (TOC). Elaborating on these difficulties, discuss how an integrated approach can help in tackling TOCs. **(250 words) 15**

पार-राष्ट्रीय संगठित अपराधों (ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स: TOCs) को रोकने, पता लगाने, जाँच करने और अभियोजित करने में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए UNODC (यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स) ने एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है। इन कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन करते हुए, चर्चा कीजिए कि किस तरह एक एकीकृत दृष्टिकोण से TOCs से निपटने में सहायता मिल सकती है।

संगठित अपराध से तात्पर्य तीन या अधिक लोगों के श्रेणीबद्ध, सोपानबद्ध, व्यावसायिक मॉडल पर आधारित ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है जो अपनी प्रकृति में अवैध हैं। उदाहरण के लिये ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग।

यही अपराध जब एक देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं तो इन्हें पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध कहते हैं उदा० के लिए दाउद अब्राहम की डी-कंपनी।

संगठित अपराध रोकने की कठिनाइयाँ :-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(क) एकस्पष्ट कानून या नीति का अभाव :- भारत में बिखरे कानूनों जैसे प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एवं मादक पदार्थों पर अन्य कानूनों के कारण बहु-आयामी अपराधों वाले अपराधों पर लगाम लगाना मुश्किल होता है।

(ख) दोहरी आपराधिकता :- विभिन्न देशों में अपराधियों के अलग मानक व कानून उदा० दाउद इब्राहिम (पाकिस्तान में)

(ग) सोपानिक क्रम होने के कारण छोटे अपराधी ही सामने आते हैं। उच्च संगठनात्मक नेताओं को पकड़ना मुश्किल होता है।

(घ) अपराध साबित होने में देरी - फास्ट ट्रैक न्यायालयों का अभाव

(ङ) पार-राष्ट्रीय अपराधों के बारे में जानकारी व डाटा का अभाव।

(च) नेता - नौकरशाही एवं अपराधियों के गठबंधन का मौजूद होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एकीकृत दृष्टिकोण का प्रभाव :- आज के सूचना क्रान्ति व तकनीक के समय में यह आवश्यक है कि संगठित व पार-राष्ट्रीय अपराधों के संबंध में निश्चित मानक तय कर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाये

लाभ

- विभिन्न देशों में सहयोग बढ़ेगा।
- 'दोहरी आपराधिकता' जैसे मुद्दों का समाधान होगा।
- डाटा-आदान-प्रदान संभव हो पायेगा।
- अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी प्रवर्तन में सहायता मिलेगी।
- उदाहरण के लिये भारत बांग्लादेश ने पशु-तस्करी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

इस प्रकार बॉर्डर प्रबंधन, स्थानीय समुदाय भागीदारी आदि के द्वारा इस दृष्टिकोण से इन अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. The Government has adopted a holistic approach built around simultaneous implementation of a security agenda, developmental activities and promotion of good governance to address the Left Wing Extremism in India. Comment. **(250 words) 15**

सरकार ने भारत में वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म) से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंडे, विकास संबंधी गतिविधियों और सुशासन के प्रचार-प्रसार के समकालिक कार्यान्वयन के चारों ओर निर्मित एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। टिप्पणी कीजिए।

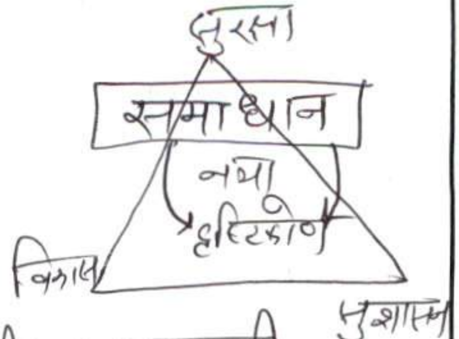

वामपंथी उग्रवाद की बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए इसके समाधान के प्रयास भी बहुआयामी होने चाहिये। केवल बंदूक से जवाब न देकर विकास व सहभागिता के साथ विचारधारात्मक आंदोलन चलाये जाने की भी आवश्यकता है जो निम्न सरकारी प्रयासों में दिखता है -

① सुरक्षा दृष्टिकोण :-

- पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना
  - पुलिस थानों को फोर्टिफाइड करना
  - नये हथियार, तकनीकों से लैस करना
  - नई आसूचना, फोरेंसिक प्रणाली पर बल

- नई केन्द्रीय बटालियन का गठन करना (कोबरा बटालियन)

② विकास संबंधी कार्य

- सड़क संपर्क योजना
- कौशल विकास हेतु 'रोशनी' योजना
- सिविक एक्शन प्रोग्राम - ताकि सुरक्षाबल विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा जैसी योजनाएँ

③ अधिशासनात्मक कार्य :-

- सहभागिता हेतु समुदाय आधारित पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समिति का गठन।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों हेतु पेसा कानून, वन अधिकार अधिनियम को पारित कर क्रियान्वित करना।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।

परन्तु इन सभी प्रयासों के बावजूद इस

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में कुछ कमियाँ विद्यमान है जैसे-

(क) केन्द्र-राज्य, राज्य-राज्य सहयोग का अभाव क्योंकि नक्सलियों का वास राज्यों के जंक्शन पर होता है

(ख) सुरक्षात्मक प्रशासन व सिविलप्रशासन में सहयोग का अभाव - शांति स्थापित होते ही विकास कार्य शुरू नहीं हो पाते।

(ग) केन्द्रीय प्रतिनियुक्तियों के कारण स्थानीय आसूचना व विशेषज्ञता को अनदेखा किया जाता है।

(घ) अभी भी तकनीकी पक्ष, पुलिस के हथियारों के उन्नयन का अभाव है

इस प्रकार कुछ कमियों के बावजूद सरकार नक्सलियों पर नियंत्रण करने में 'समाधान' सिद्धान्त का प्रयोग करने में सफल रही है। नक्सली हिंसा में 2013-17 के मध्य 34% की कमी इसका उदाहरण है